RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 06 JULY 2022 TO 12 JULY 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 43 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पादों पर टैक्स से भरेगा सरकार का खजाना Page 2

गैर ब्रांडेड खाद्य सामग्री पर जीएसटी लागू करने का इंदौर के व्यापारियों ने किया विरोध Page 3

एल्सटॉम को भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए अनुबंध मिला Page 5

editoria!

प्लास्टिक पर लगाम

भारत अगर एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में वाकई कामयाब हो गया, तो यह दुनिया के लिए भी एक बड़ी सफलता होगी। एलईडी बल्ब का उपयोग बढ़ाकर और पेट्रोल में पर्यावरण अनुकूल जरूरी सुधार के बाद भारत जिस गर्व का एहसास कर रहा है, उसमें आने वाले महीनों में इजाफा होने वाला है। देश में लगभग 19 तरह के प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने निस्संदेह सराहनीय काम किया है। एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने उत्पादों में करने वाली कंपनियां समय मांग रही थीं, उन्हें लेकिन समय न देकर सरकार ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया है, वह आने वाले दिनों में भी बनी रहनी चाहिए। लगभग 1.4 अरब लोगों के इस देश में अनेक उत्पादों का कलेवर बदलने वाला है। पिछले वर्षों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिशें हुई तो हैं, पर बहुत कामयाबी नहीं मिली है। प्लास्टिक की सहज उपलब्धता और किफायती होने की वजह से इसका इस्तेमाल रोके नहीं रुक रहा है। बीच में प्लास्टिक बैग पर कुछ लगाम लगी थी, लेकिन अब फिर इसका इस्तेमाल पहले की तरह दिखने लगा है। अब समय आ गया है कि सरकार पूरी कड़ाई से इस प्रतिबंध को लागू करे। खतरनाक बात यह है कि भारत सालाना लगभग 1.40 करोड़ टन प्लास्टिक का उपयोग करता है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक संगठित व्यवस्था का अभाव है और देश में जगह-जगह प्लास्टिक कचरा फैला दिखता है। कई जगह यह मुसीबत बन चुका है। हम यह समझने को तैयार नहीं हैं कि अगर प्लास्टिक को ठीक से ठिकाने लगाया जाए, तब भी कई साल लग जाते हैं। अगर ठिकाने न लगाएं, तो मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अनुचित तरीके से फेंके गए बैगों से जल प्रदूषित हो गए हैं, सीवर बंद हो गए हैं और समुद्री जीवों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक महासागरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। अतः जरूरी है कि दुनिया युद्ध स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करे और धरती को स्वस्थ मानव जीवन लायक बनाए रखे। जो थोड़ा सा प्लास्टिक रहे, उसे बार-बार उपयोग लायक बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र लगातार बताता आ रहा है कि प्लास्टिक की थैलियों से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। अगर प्लास्टिक लगातार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, तो ऐसे प्लास्टिक की सतह से दो ग्रीनहाउस गैसों- मीथेन और एथिलीन की बड़ी मात्रा पैदा होती है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही हल्के प्लास्टिक बैग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर की 90 से अधिक सरकारों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया है। एशिया में बांग्लादेश ने इस दिशा में सबसे पहले साल 2002 में कदम उठाया था। कुछ देश जुर्माना लगा रहे हैं, तो कुछ देशों ने पूरी तरह से प्रतिबंध का सहारा लिया है। इस मामले में एकरूपता के लिए भी प्रयास करने चाहिए। प्रतिबंध लगाने के साथ ही, सरकारों को विकल्प की दिशा में भी पहल करनी चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज, जूट, पत्तों, कपड़ों, अल्युमिनियम की थैलियों को बढ़ावा देना चाहिए। इन सामग्रियों के प्रचार व व्यवहार पर निवेश करना चाहिए। लोगों को बेहतर विकल्प मिलें, तो प्लास्टिक का उपयोग निश्चित ही कम होगा।

जीएसटी के स्लैब अब हो सकते हैं चार से तीन

बिजली और ईंधन भी आ जाएंगे इसके दायरे में

नई दिल्ली। एजेंसी

उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष संजीव बजाज ने मंगलवार को जीएसटी ढांचे को सरल बनाने की वकालत करते हुए कहा कि बिजली के साथ ईंधन को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके साथ ही बजाज ने जीएसटी के कर स्लैब की संख्या को भी चार से घटाकर तीन करने का सुझाव दिया। बजाज ने समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को अधिक सरल बनाने के लिए कुछ असंगतियों को दूर करना होगा और बिजली, ईंधन जैसे उत्पादों को भी इस कर के दायरे में लाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "अगर हम ऐसा करते हैं, तो जीएसटी की संरचना अधिक सरल होगी, लागत में कमी आएगी और उद्योग जगत अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो पाएगा।" उन्होंने विलासिता वाले उत्पादों को 28 प्रतिशत के ऊंचे कर स्लैब में रखे जाने को सही ठहराते हुए कहा, "हमारा मानना है कि जीएसटी कर ढांचे को सरलीकृत कर तीन स्लैब बनाए जा सकते हैं। अब इस कर प्रणाली को लागू हुए पांच साल बीत चुके हैं और हमारे पास अनुभव भी है लिहाजा इस पर चर्चा की जा सकती है।"

जीएसटी के फिलहाल चार स्लैब हैं जो क्रमशः पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। सोने और रत्न एवं आभूषण के लिए कर की अलग दरें हैं। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती सेहत के मुद्दे पर कहा कि रिजर्व बैंक इसे काबू में करने की अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मानसून अच्छा रहता है तो मुद्रास्फीति में कमी आनी चाहिए। बजाज ने कहा कि बीते दो वर्षों में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की वजह से भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है।

जीएसटी से छूट वाली सेवाओं की संख्या घटाने की जरूरत

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने मंगलवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत छूट वाले उत्पादों की सूची को कम करने की जरूरत है। विशेषरूप से सेवा क्षेत्र के लिए ऐसा करना जरूरी है। बजाज ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की कोशिश अगले दो-तीन वर्षों में जीएसटी प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करने की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के काम में मंत्री समूह लगा हुआ है लेकिन इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा, "अब भी कई उत्पादों एवं सेवाओं को जीएसटी से छूट मिली हुई है जिनमें सेवाओं की संख्या ज्यादा है। इनको कम करने के लिए काम करने की जरूरत है।"

अस्पतालों में गैर-आईसीयू कमरों के 5,000 रुपये से अधिक किराये पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को लेकर उठ रहे सवालों पर बजाज ने कहा कि इतना किराया लेने वाले अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा, "अगर मैं अस्पताल के कमरे का 5,000 रुपये किराया दे सकता हूं तो मैं जीएसटी के 250 रुपये भी दे सकता हूं।" उन्होंने कहा कि सकल जीएसटी राजस्व में 28 प्रतिशत कर स्लैब का हिस्सा 16 प्रतिशत है। वहीं सबसे अधिक 65 प्रतिशत राजस्व 18 प्रतिशत के कर स्लैब से आता है। वहीं पांच प्रतिशत और 12 प्रतिशत कर स्लैब का राजस्व में योगदान क्रमशः 10 प्रतिशत और आठ प्रतिशत है।

एनटीपीसी की खानों से अप्रैल-जून में कोयला उत्पादन 61 प्रतिशत बढ़कर 42.20 लाख टन हुआ

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी का कोयला उत्पादन अप्रैल-जून तिमाही में 61 प्रतिशत बढ़कर 42.40 लाख टन हो गया। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि एक साल पहले इसी अवधि में उसका उत्पादन 26.40 लाख टन था। एनटीपीसी ने बयान में कहा, "इस समय चालू तीन कोयला खदानों: पकरी-बरवाडीह (झारखंड), दुलंगा (ओडिशा) और तलाईपल्ली (छत्तीसगढ़) ने 42.40 लाख टन कोयला उत्पादन हासिल करने में योगदान दिया।" बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 42.40 लाख टन कोयले का उत्पादन, पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 61 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने बताया कि जून, 2022 में कोयले का उत्पादन लगभग दोगुना होकर 15.55 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 7.73 लाख टन था। एनटीपीसी ने समीक्षाधीन तिमाही में अपने बिजली संयंत्रों तक 41.74 लाख टन कोयला रवाना किया। एनटीपीसी ने कहा कि उसने झारखंड स्थित अपनी चट्टी-बरियातू कोयला खान में भी खनन कार्य शुरू कर दिया है। इस खदान से कोयले की आपूर्ति एनटीपीसी के बाढ़ बिजली केंद्र को की जाएगी।

एलपीजी के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि, 14.2 किलो का सिलेंडर अब 1,053 रुपये का

नयी दिल्ली। घरेलू रसोई गैस के दाम में बुधवार को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई। मई महीने से एलपीजी की दरें तीसरी बार बढ़ाई गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1,053 रुपये हो गई है। देश के अधिकांश शहरों में अब सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है लिहाजा खरीदारों को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर ही खरीदने पड़ रहे हैं। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन पाने वाले लाभार्थियों को ही सिर्फ एलपीजी सब्सिडी दे रही है।

पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पादों पर टैक्स से भरेगा सरकार का खजाना

एक फैसले से होगा 12 अरब डॉलर का फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन और ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने से सरकार को बड़ा फयदा होगा। इस टैक्स से सरकार को चालू वित्त वर्ष की बची हुई अवधि में करीब 12 अरब डॉलर (94,800 करोड़ रुपये) मिलेंगे। मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को यह अनुमान जताया है। साथ ही मूडीज ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ओएनजीसी जैसी कंपनियों के मुनाफे में कमी आएगी।

सरकार ने एक जुलाई को पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर और घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। साथ ही निर्यातकों के लिए पहले घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया। मूडीज ने इन नए करों पर अपनी टिप्पणी में कहा, ''कर वृद्धि से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे भारतीय कच्चे तेल के उत्पादकों और तेल निर्यातकों के मुनाफे में कमी आएगी।''

इतना देना होगा टैक्स

सरकार की घोषणा के बाद भारतीय तेल कंपनियों को पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर छह रुपये प्रति लीटर (लगभग 12.2 डॉलर प्रति बैरल) और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर (लगभग 26.3 डॉलर प्रति बैरल) का भुगतान करना होगा। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते घरेलू उत्पादकों को 23,250 रुपये प्रति टन (करीब 38.2 डॉलर प्रति बैरल) का टैक्स देना होगा।

सरकार को मिलेगा 12 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त रेवेन्यू

रेटिंग एजेंसी ने कहा, ''हमारा अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 2022-23 की बाकी अवधि में लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त राजस्व हासिल करेगी। हमारा यह अनुमान वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में कच्चे तेल के उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर आधारित है। इस अतिरिक्त राजस्व से मई के अंत में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई कमी के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में मदद मिलेगी।''

अस्थायी हो सकता है यह टैक्स

मूडीज ने आगे कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि यह सरकारी उपाय अस्थायी होगा और करों को आखिर में बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इन स्थितियों में मुद्रास्फीति, बाहरी संतुलन और मुद्रा मूल्यह्रास जैसी चीजें शामिल हैं।''

घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन और ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर से सरकार को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में करीब 12 अरब डॉलर (94,800 करोड़ रुपये) मिलेंगे। मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को यह अनुमान जताते हुए कहा कि इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ओएनजीसी जैसी कंपनियों के मुनाफे में कटौती होगी।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे चढ़कर 79.24 पर

सेंसेक्स 317 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 15,892 पर

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में नौ पैसे चढ़कर और अपने रिकॉर्ड निचले स्तर में सुधार करते हुए 79.24 पर खुला।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.24 पर खुला जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त दर्शाता है। शुरुआती सौदों में यह 79.24 के ऊंचे स्तर और 79.31 के निम्न स्तर तक गया। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.33 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत गिरकर 106.45 पर आ गया। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.14 प्रतिशत चढ़कर 103.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजार में लंबे समय के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के शुद्ध लिवाली करने के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 317 अंक से अधिक चढ़ गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 317.52 अंक बढ़कर 53,451.87 पर पहुंच गया। दूसरी ओर एनएसई निफ्टी 81.8 अंक चढ़कर 15,892.65 पर था। पिछले सत्र में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 100.42 अंक यानी 0.19 प्रतिशत टूटकर 53,134.35 अंक पर बंद हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24.50 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 15,810.85 अंक पर बंद हुआ था। अन्य एशियाई बाजारों में तोक्यो, शंघाई, हांगकांग और सियोल के बाजार नुकसान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को लाभ के साथ बंद हुए।

इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.31 प्रतिशत बढ़त के साथ 104.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 1,295.84 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे।

खिलौना उद्योग को विनिर्माण, निर्यात बढ़ाने के लिये बड़ी सोच की जरूरत: वाणिज्य मंत्रालय

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को घरेलू खिलौना उद्योग से विनिर्माण और निर्यात को गति देने के लिये बड़ी सोच और क्षमता निर्माण पर काम करने को कहा। उद्योग संवर्द्धन और आतंरिक व्यापार विभाग में अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने कहा कि सरकार के आयात शुल्क बढ़ाने और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जैसे कदमों से आयात में कमी लाने तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिली है। और अब उद्योग को बड़ी सोच के साथ काम करने की जरूरत है।

अग्रवाल ने प्रगति मैदान में खिलौना मेले में संवाददाताओं से कहा, ''राजस्व बढ़ा है लेकिन यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली कंपनियां) बनने के लिये उद्योग को एक अलग स्तर पर पहुंचना होगा। उन्हें अपने प्रबंधन को पेशेवर बनाने के साथ क्षमता निर्माण पर काम करने की जरूरत है।'' कोविड महामारी के कारण मेले का आयोजन तीन साल के अंतराल के बाद किया गया है। 96 स्टॉल देश में बने खिलौनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये खिलौनों पर मूल सीमा शुल्क फरवरी, 2020 में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही फरवरी, 2020 में खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश जारी किया गया। इसके तहत खिलौनों को प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। यह घरेलू और उन विदेशी विनिर्माताओं पर लागू होता है जो भारत को अपने खिलौने निर्यात करना चाहते हैं। अग्रवाल के अनुसार, देश में खिलौनों का आयात 2018-19 में 30.4 करोड़ डॉलर का था जो 2021-22 में घटकर 3.6 करोड़ डॉलर पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ निर्यात 2018-19 में 10.9 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 17.7 करोड़ डॉलर पहुंच गया।

भारत, ऑस्ट्रेलिया का दुर्लभ खनिज क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने का निर्णय

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिज से जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने का संकल्प जताया। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर बातचीत के दौरान यह संकल्प जताया। भारत महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आस्ट्रेलिया लिथियम, कोबाल्ट और वैनेडियम जैसे खनिज का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिये महत्वपूर्ण माना जाता है।

कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी और ऑस्ट्रेलिया की संसाधन मंत्री मेडेलिन किंग ने दुर्लभ खनिज क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर बातचीत की। यह बातचीत मार्च में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के दौरान किये गये निर्णय के अनुरूप है। जोशी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बयान के अनुसार बैठक में किंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया तीन साल की भारत-

ऑस्ट्रेलिया 'दुर्लभ खनिज निवेश भागीदारी के लिये 58 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (39.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर) देगा। किंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत महत्वपूर्ण खनिजों पर एक स्वभाविक भागीदार हैं। दोनों देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बयान के अनुसार जोशी ने कहा, ''हमने हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस (सीएमएफओ) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के लिये महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना है।'' उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन में ऑस्ट्रेलिया की लिथियम और कोबाल्ट खनिज संपत्ति के संयुक्त रूप से जांच-परख का कार्य शामिल है। जोशी ने कहा, ''सीएमएफओ और भारतीय संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड दोनों संयुक्त रूप से 60 लाख डॉलर (अमेरिकी) की शुरुआती राशि के साथ जांच-परख का काम करेंगे। जांच-परख का काम पूरा होने और संभावित परियोजनाओं की पहचान के बाद हम निवेश अवसरों का पता लगाएंगे।''

गैर ब्रांडेड खाद्य सामग्री पर जीएसटी लागू करने का इंदौर के व्यापारियों ने किया विरोध

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जीएसटी काउंसिल ने बीते सप्ताह हुई बैठक के बाद गैर ब्रांडेड यानी लेबल वाली खाद्य सामग्री को भी पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में ले लिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद हुई इस घोषणा का विरोध शुरू हो गया है। 18 जुलाई से नए नियम को लागू करने की बात कही गई है। हालांकि नए नियमों को लेकर अब भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। निर्णय के खिलाफ व्यापारी एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को इंदौर व्यापारी संगठनों ने बैठक बुलाकर महंगाई बढ़ने पर चिंता जताई।

जीएसटी में अब तक गैर ब्रांडेड खाद्य सामग्री को टैक्स के दायरे से मुक्त रखा जा रहा है। सीए भरत नीमा के अनुसार अब तक शर्त रखी गई थी कि खाद्य सामग्री जो अनब्रांडेड है, उस पर एक्शनेबल क्लेम नहीं लिया जाता, तो वह जीएसटी से मुक्त रखी जाएगी। इस निर्णय के बाद देश के तमाम अनाज, दाल, दलहन कारोबारी बीते पांच वर्षों से अपनी पैकिंग के नीचे एक्शनेबल क्लेम नहीं लेने की सूचना लिखवाकर टैक्स से छूट

हासिल कर रहे थे। अब जीएसटी एक्ट में ब्रांडेड शब्द को बदलकर उसके साथ लेबल्ड फूड भी लिखा जा रहा है। इस नियम के लागू होने से हर तरह की अनाज, दाल, मैदा, आटा जैसे कृषि उत्पाद और सामग्री जीएसटी के दायरे में आ जाएगी।

10 से 15 फीसद महंगी हो जाएंगी जरूरत की वस्तुएं - इंदौर चावल व्यापारी एसोसिएशन ने खाद्य सामग्री अनाज, दालों को जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध में बैठक ली। एसोसिएशन ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया और कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेशभर के व्यापारियों का समर्थन मांग कर ज्ञापन दिल्ली भेजा जाएगा। दरअसल, पांच प्रतिशत टैक्स लगाने का असर होगा कि आम लोगों के लिए अनाज, आटा जैसी आम जरूरतों की वस्तुएं 10 से 15 प्रतिशत तक महंगी हो जाएगी। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार भले ही विलासिता की वस्तुओं पर भारी भरकर कर लगा दे, लेकिन आम लोगों का खाद्यान्न महंगा न करें। ऐसी वस्तुओं पर कारोबार ही 1 से 2 प्रतिशत के मुनाफे पर होता है। जीएसटी के दायरे में आने पर ई-वे बिल की बाध्यता भी लागू हो जाएगा। ऐसे में कारोबार की मुश्किल बढ़ जाएगी। व्यापारियों का जीएसटी की कार्रवाई का खर्च भी टैक्स के साथ जुड़ जाएगा।

जैविक उत्पादों के परीक्षण के लिए सभी जिलों में प्रयोगशालाएं बनेंगी, अमूल होगी नोडल एजेंसी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने जैविक उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन उत्पादों के वैश्विक विपणन में उनकी मदद करने के लिए प्रमुख डेयरी संस्था अमूल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने का फैसला किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यह घोषणा की। सरकार सहकारी समितियों के उत्पादों की ब्रांडिंग और विदेशी निर्यात खेपों के लिए दो प्रतिबद्ध 'निर्यात गृह' भी स्थापित करेगी।

सहकारिता के 100वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अमूल को जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता के परीक्षण और प्रमाणन का काम दिया गया है। शाह ने कहा, ''अमूल इन सभी जैविक उत्पादों को भारत के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में बेचने के लिए अपने ब्रांड के साथ काम करेगी ताकि जैविक खेती में लगे किसानों को अपने उत्पादों की कम से कम 30 प्रतिशत अधिक कीमत मिल सके।''

उन्होंने कहा कि मिट्टी और जैविक उत्पादों के परीक्षण के लिए देश के प्रत्येक जिले में प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अमूल (अन्य सहकारी समितियां भी शामिल होंगी) के तहत एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। अमूल नोडल एजेंसी होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि देशभर में सहकारी संस्थाओं के उत्पादों की गुणवत्ता का ख्याल रखने के लिए दो बड़े सहकारी निर्यात घरानों को पंजीकृत किया जाएगा, उनके उत्पादन चैनल को वैश्विक बाजार के समतुल्य बनाया जाएगा और इन उत्पादों के निर्यात का माध्यम बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने फसल उत्पादकता को बेहतर करने के लिए बीज खंड में सुधार करने को इफको और कृभको जैसी दो बड़ी सहकारी समितियों को साथ लिया है। शाह ने बताया कि सरकार ने सहकारी समितियों को सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम के माध्यम से खरीदारी करने की अनुमति दी है। सहकारिता मंत्रालय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का एक डेटाबेस भी बना रहा है। शाह ने बताया कि सरकार ने प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो सहकारी क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ गठजोड़ करेगा।

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि सहकारी समितियों को बचत करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि सभी सहकारी समितियां बचत की आदत विकसित कर लें तो उन्हें कभी भी धन सृजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रूपाला ने सुझाव दिया कि सहकारी समितियों की रैंकिंग उनकी बचत क्षमता और बचत की राशि के अनुसार की जा सकती है।

जीएसटी से छूट वाली सेवाओं की संख्या घटाने की जरूरत : राजस्व सचिव

नयी दिल्ली। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने मंगलवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत छूट वाले उत्पादों की सूची को कम करने की जरूरत है। विशेषरूप से सेवा क्षेत्र के लिए ऐसा करना जरूरी है। बजाज ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की कोशिश अगले दो-तीन वर्षों में जीएसटी प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करने की है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के काम में मंत्री समूह लगा हुआ है लेकिन इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा, ''अब भी कई उत्पादों एवं सेवाओं को जीएसटी से छूट मिली हुई है जिनमें सेवाओं की संख्या ज्यादा है। इनको कम करने के लिए काम करने की जरूरत है।''

अस्पतालों में गैर-आईसीयू कमरों के 5,000 रुपये से अधिक किराये पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को लेकर उठ रहे सवालों पर बजाज ने कहा कि इतना किराया लेने वाले अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा, ''अगर मैं अस्पताल के कमरे का 5,000 रुपये किराया दे सकता हूं तो मैं जीएसटी के 250 रुपये भी दे सकता हूं।'' उन्होंने कहा कि सकल जीएसटी राजस्व में 28 प्रतिशत कर स्लैब का हिस्सा 16 प्रतिशत है। वहीं सबसे अधिक 65 प्रतिशत राजस्व 18 प्रतिशत के कर स्लैब से आता है। वहीं पांच प्रतिशत और 12 प्रतिशत कर स्लैब का राजस्व में योगदान क्रमशः 10 प्रतिशत और आठ प्रतिशत है।

केयर हॉस्पिटल्स ने सी एच एल हॉस्पिटल इंदौर का अधिग्रहण किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल्स, जो टीपीजी ग्रोथ मैनेज्ड एवरकेयर फंड का प्रमुख संस्थान है तथा भारत का प्रतिष्ठित अग्रणी हॉस्पिटल नेटवर्क है, ने मध्यप्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसके अंतर्गत इंदौर के सी एच एल हॉस्पिटल के अधिग्रहण की घोषणा की। वर्ष 2001 में स्थापित कन्वीनियंट हॉस्पिटल लिमिटेड (सीएचएल) मध्यभारत में स्थापित किया गया पहला कारपोरेट हॉस्पिटल था और अपने मजबूत क्लीनिकल विशेषज्ञता के लिए कार्डियोलॉजी/ कार्डियक सर्जरी, न्यूरोसाइंस, जी आई, लिवर ट्रांसप्लांट रीनल साइंस तथा क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त रहा।

केयर हॉस्पिटल्स वर्ष 1997 में एकमात्र कार्डियक हॉस्पिटल के रूप में हैदराबाद में प्रारंभ हुआ था जिसमें 100 बेड्स एवं 20 कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे। केयर ग्रुप आज भारत के अग्रणी मल्टी केयर हॉस्पिटल के रूप में उन्नति कर चुका है जिसमें 6 राज्यों में 15 फसिलिटीज़ सम्मिलित है और 30 क्लीनिकल विशेषज्ञता उपलब्ध है और 2400 से ज्यादा बेडस हैं। यह भारत का पहला हॉस्पिटल समूह है जिसमें देश में 2 टीयर्स श्रेणी के शहरों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है।

इस अधिग्रहण के बारे में केयर हॉस्पिटल्स समूह के सीईओ जसदीप सिंह ने बतलाया कि – 'हम सी एच एल हॉस्पिटल को केयर ग्रुप में सम्मिलित होने का स्वागत करते हैं और क्लीनिकल केयर में, मरीजों को परस्पर विशेषज्ञता के उच्च सेवाओं को मध्य भारत में मरीजों तक पहुंचाने की अपार संभावनाओं से उत्साहित हैं। सी एच एल के साथ अपनी भागीदारी से केयर हॉस्पिटल्स टियर 2 शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख प्रदाता के रूप में नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करता है'ध केयर हॉस्पिटल्स ग्रुप से जुड़े 1200 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर एवं 6000 कर्मियों के साथ प्रतिवर्ष लाखों मरीजों का इलाज किया जाता है और पिछले 25 वर्षों में विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों जैसे कार्डियक साइंस, अंकोलाजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंस, रीनल साइंस, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी व हिपेटोलाजी, ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ईएनटी, बस्क्युलर सर्जरी, इंटीग्रेटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में उत्कृष्टता प्राप्त की है। यह घोषणा केयर हॉस्पिटल्स की महत्वपूर्ण 25वीं सालगिरह के गौरवशाली अवसर पर, क्लीनिकल उत्कृष्टता की मजबूत परंपरा आगे बढ़ाने की कोशिशों से जुड़ी है।

सी एच एल हास्पिटल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री राजेश भार्गव ने कहा कि 'हम तेजी से उन्नति कर रहे सी एच एल हास्पिटल इन्दौर को और आगे बढ़ाने की केयर हॉस्पिटल्स ग्रूप की पहल का स्वागत करते हैं। विगत 21 वर्षों में, सी एच एल हास्पिटल के क्लिनिकल विशेषज्ञ डाक्टर्स की टीम को उल्लेखनीय उपलब्धियाँ मिली है तथा अनेकों सम्मान भी प्राप्त किये है। इस नये जुड़ाव के साथ, हमारी टीम्स, केयर हॉस्पिटल्स के सीएचएल हास्पिटल को मध्यभारत मे, उन्नति की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के प्रयासों को पूरा सहयोग देने तत्पर है 'ध केयर हॉस्पिटल्स हास्पिटल के अध्यक्ष श्री विशाल बाली ने कहा कि 'भारत के भविष्य की विकास योजना तथा 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वाकांक्षा 2 टीयर शहरो की उन्नति से ही पूरी हो सकेगी।

तुर्की के राष्ट्रपति ने चली दुनिया से उलटी चाल, देश को पड़ गए खाने के लाले

नई दिल्ली। एजेंसी

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन की एक चाल उनके देश के लिए भारी पड़ी और लोगों के सामने खाने के लाने पड़ गए हैं। जून में देश में महंगाई करीब 80 फीसदी पर पहुंच गई है जो दो दशक में सबसे अधिक है। तुर्की में जून 2021 की तुलना में इस बार जून में कंज्यूमर प्राइजेज 78.6 फीसदी तेजी से बढ़ी। खासकर खानेपीने की चीजों और ट्रांसपोर्टेशन की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल में देश में खानेपीने की चीजों की कीमत दोगुनी हो गई है। एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक पिछले एक साल में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में 123 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। हाल के महीनों में देश में महंगाई में बहुत तेजी आई है। इस साल डॉलर की तुलना में तुर्की की करेंसी लीरा की कीमत में 20 फीसदी से अधिक गिरावट आई है। दुनिया के दूसरे कई देशों में भी महंगाई चरम पर है लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति के एक कदम ने देश में स्थिति बदतर कर दी। दुनियाभर के सेंट्रल बैंक महंगाई को काबू में करने के लिए नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति ने इसके उलट फैसला किया। सितंबर में उन्होंने रूल बुक से हटकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने महंगाई कम करने के लिए नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करने के बजाय इसमें कमी का फैसला किया। इसके बाद तुर्की के सेंट्रल बैंक ने दरों को घटाना शुरू कर दिया। इससे देश में महंगाई की स्थिति बद से बदतर हो गई। बाकी कसर लीरा में गिरावट ने पूरी कर दी। लीरा में गिरावट के कारण आयात करना महंगा हो गया।

तुर्की के राष्ट्रपति ने अपनी मॉनीटरी पॉलिसी का बचाव किया है। उनका तर्क है कि नीतिगत दरों में कमी से महंगाई में कमी आएगी। इससे उत्पादन और निर्यात में तेजी आएगी। उन्होंने देश की आर्थिक बदहाली के लिए विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार बताया है। देश के वित्त मंत्री नूरेद्दीन नेबाती ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि दुनियाभर में कमोडिटी की कीमतों में तेजी से जून में महंगाई में तेजी आई। उन्होंने कहा कि लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इनमें सेल्स टैक्स में कमी और सब्सिडी शामिल है।

बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में सुधार ला सकती हैं पीपीपी परियोजनाएं : मंत्री

मुंबई। एजेंसी

भारतीय बंदरगाहों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश की स्थिति को मजबूत करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने यहां समुद्री सार्वजनिक-निजी भागीदारी सम्मेलन-2022 को संबोधित करते हुए कहा कि निजी कंपनियों को शामिल करने से बंदरगाह क्षेत्र की दक्षता में सुधार हुआ है और आय वृद्धि में मदद मिली है।

इस सम्मेलन का आयोजन प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी निवेश के 25 वर्ष पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) और मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण (एमबीपीए) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। उन्होंने कहा, ''पीपीपी माध्यम बुनियादी ढांचे के विकास का सही तरीका बन गया है। जब हम इन 25 वर्षों के फलदायी उत्सव का जश्न मना रहे हैं, तो हमें एक सहायक वातावरण तैयार करके भविष्य के पीपीपी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है।'' नाइक ने कहा कि जब 1997 में बंदरगाह के निजीकरण कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई गई, तो विदेशी निवेश सहित बंदरगाह क्षेत्र में नया निवेश देखा गया। उन्होंने कहा, ''पीपीपी परियोजनाएं भारतीय बंदरगाहों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।''

नवनीत एजुकेशन का ब्रांड युवा का स्टूडेंट्स की स्कूल में वापसी का स्वागत

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

दो वर्षों से अधिक समय के बाद, पहली बार बच्चों के मन में वही पुराने भाव जाग उठे हैं कि हम वापस स्कूल कब जायेंगे। आखिरकार, नए शैक्षणिक वर्ष की सामान्य शुरुआत हो रही है और अब बच्चों का फिर से स्कूल में स्वागत करने का वक्त आ गया है। युवा, जो 'नवनीत एजुकेशन' के घराने का प्रमुख स्टेशनरी ब्रांड है, बिल्कुल नई डिजाईन की गई स्टेशनरी रेंज के साथ स्टूडेंट्स का स्कूल में स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए इसने 'बैक टु स्कूल' कैंपेन का सहारा लिया है। इस कैंपेन का शुभारम्भ करते हुए युवा के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर और प्रवक्ता, अभिजीत सान्याल ने कहा कि, 'स्टूडेंट्स स्कूल में वापस लौट रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बिलकुल नए कैंपेन, 'हैप्पी होके चले स्कूल हम' की शुरुआत करके इस अवसर का जश्न मनाने का आइडिया आया। हमने अपनी डिजिटल एजेंसी 'ऐन्ट्स डिजिटल' के साथ मिलकर एक रोमांचक फिल्म बनाई है जिसमें फिर से स्कूल में वापसी करने वाले बच्चों के आनंद को दर्शाया गया है। बिलकुल नई उत्पाद श्रृंखला और नया बीटीएस कैंपेन स्टूडेंट्स को क्लासरूम से जुड़ने और सामान्य अवस्था प्राप्त करने में मदद करेगा। हमारे सामने कागज़ की लागत के मामले में चुनौतीयाँ खड़ी हैं और हमने अपने ग्राहकों पर इसका बोझ कम-से-कम करने के लिए हर प्रयास किया है। लेकिन बच्चों को स्कूल में वापस जाने के दृश्य ने हम सभी के लिए उत्साह का भाव उत्पन्न किया है।' ब्रांड फिल्म, 'हैप्पी होके चले स्कूल हम' के लॉन्च पर ऐन्ट्स डिजिटल के सीईओ, संजय अरोड़ा ने कहा कि, 'यह हमारी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है जो जीवंत होकर सामने आई है। पूरी फिल्म सभी माताओं की कहानी बयां करती है जो इन बीते दो वर्षों में अपने बच्चों के सफ़र को देख रही हैं। साथ ही यह स्कूल वापस जाने के लिए तैयारी में लगे बच्चों के नए उत्साह की अभिव्यक्ति है। इस फिल्म को बनाने में हमें काफी मजा आया और हमें पक्का यकीन है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स को भी यह फिल्म पसंद आएगी।' कई दौर के लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण पिछले दो वर्षों में बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षणिक जीवन बाधित हुआ है। इस अवधि में अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, जैसे कि क्लासरूम में लाइव उपस्थित होना, टीचर के साथ बातचीत करना, सहपाठियों के साथ खेल के मैदान में कसरत और खेल-कूद करना सब बंद हो गए थे।

एल्सटॉम को भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए अनुबंध मिला

मेट्रो ट्रेन और सीबीटीसी सिग्नलिंग की आपूर्ति करेगी एल्सटॉम 387 मिलियन पाउंड के खरीद आदेश अनुबंध में ट्रेन कंट्रोल और टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम की आपूर्ति भी शामिल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

फुर्तीली और सतत गतिशीलता में वैश्विक नेतृत्वकर्ता, एल्सटॉम को मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) से भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं के लिए 15 सालों के व्यापक रखरखाव के साथ 156 मोविया मेट्रो कारों की आपूर्ति करने का अनुबंध मिला है। यह परियोजना दोनों शहरों के 5.7 मिलियन से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करेगी। 387 मिलियन पाउंड (3200 करोड़ रु. से ज्यादा) के इस खरीद आदेश में कम्युनिकेशंस बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेन कंट्रोल एवं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स की आधुनिकतम पीढ़ी की स्थापना शामिल है। इन दोनों के साथ सात सालों का विस्तृत रखरखाव भी शामिल है।

एल्सटॉम 3-कार के विन्यास में 52 मानक नाप मोविया मेट्रो पैसेंजर ट्रेन सेट के प्रारूपण, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन करेगा। 27 ट्रेन सेट भोपाल के लिए होंगी और 25 ट्रेनसेट इंदौर के लिए होंगी। सवली (गुजरात) में एल्सटॉम की अत्याधुनिक रोलिंग स्टॉक निर्माण सुविधा में बनने वाली ये आधुनिक, कम वजनी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की सर्वोच्च गति से भोपाल में 30 स्टेशनों के साथ 31 किलोमीटर लंबे मार्ग और इंदौर में 29 स्टेशनों के साथ 31.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलेंगी। भारत में आगरा-कानपुर मेट्रो परियोजनाओं के बाद एल्सटॉम को यह दूसरा संयुक्त खरीद आदेश मिला है।

Olivier Loison, Managing Director, Alstom India cluster ने कहा, ''हमें एमपीएमआरसीएल से यह दूसरा महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त होने की खुशी है। हमारा यह गठबंधन भोपाल एवं इंदौर शहरों के लिए एक प्रभावशाली एवं सतत जन परिवहन व्यवस्था का मजबूत आधार रखेगा। भारत जन परिवहन के लिए हरित और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करने के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है और एल्सटॉम को भारत के इस सफर का दीर्घकालिक भागीदार बनने तथा देश की वृद्धि में योगदान देने पर गर्व है। आगरा-कानपुर मेट्रो अनुबंध के बाद यह अनुबंध हमारे ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक परिवहन समाधान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को साबित करता है।''

इससे पूर्व एल्सटॉम इंडिया भारत में दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि जैसे बड़े शहरों और विश्व में सिडनी, क्वींसलैंड, और मॉन्ट्रील के लिए विश्वस्तरीय मेट्रो ट्रेंस की आपूर्ति कर चुका है। मौजूदा समय में कंपनी आगरा-कानपुर, मुंबई मेट्रो लाईन 3 के लिए मेट्रो ट्रेन और भारत के पहले मध्यम उच्च गति दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के लिए आधुनिक ट्रेन बना रही है।

मोविया मेट्रो परिवार प्रमाणित और विश्वसनीय उपकरणों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। हल्की एवं मजबूत स्टील कार बॉडी से बनाई गई ये वातानुकूलित कारें पर्यावरणप्रेमी डिज़ाईन पर केंद्रित रहकर विकसित की गई हैं, ताकि खतरनाक पदार्थों को खत्म कर मुसाफिरों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। इन ट्रेन में रिजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ आधुनिक एवं कम ऊर्जा द्वारा चलने वाला प्रोपल्ज़न सिस्टम है, जिसके कारण ये परिवहन के अन्य माध्यमों का एक सतत विकल्प हैं और बिजली की खपत में कमी लाती हैं। मोविया मेट्रो की आपूर्ति दुनिया के अनेक शहरों, जैसे लंदन, दिल्ली, स्टॉकहोम, और सिंगापुर में की जा चुकी है। छः औद्योगिक स्थलों और चार अभियांत्रिकी केंद्रों के साथ एल्सटॉम घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए आपूर्ति करने के लिए भारत में मजबूत स्थिति में है। भारत में एल्सटॉम के पास 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम है। कंपनी इस साल अपने कार्यबल में 15 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहती है।

Single Use Plastic Ban:

अमूल, मदर डेयरी, डाबर, पारले इन्होंने पहले दिन ही दिखा दिया दम

नई दिल्ली। एजेंसी

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से पहले भले ही कुछ कंपनियां प्रतिरोध कर रही थीं। लेकिन जैसे ही यह फैसला लागू हुआ, इस पर अमल होना शुरू हो गया। रोजमर्रा के सामान बनाने वाली बड़ी कंपनियों एवं कृषि-खाद्य इकाइयों ने फलों के जूस एवं डेयरी उत्पादों के पैक के साथ कागज से बने स्ट्रॉ की पेशकश की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सहकारी क्षेत्र के संगठन अमूल और मदर डेयरी के साथ ही डाबर और पारले एग्रो जैसी प्रमुख कंपनियों ने टेट्रा पैक के साथ अब प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह कागज से बने स्ट्रॉ एवं अन्य वैकल्पिक समाधानों की पेशकश करनी शुरू कर दी है।

विकल्प मिलना आसान नहीं

एफएमसीजी कंपनियां इस समय प्लास्टिक के स्ट्रॉ के बदले कागज के बने स्ट्रॉ दे रही हैं। लेकिन यह किफायती और कारगर विकल्प नहीं है। उद्योग निकाय एक्शन अलायंस फॉर रिसाइक्लिंग बीवरेज कार्टंस (एएआरसी) ने कहा कि एफएमसीजी कंपनियों को प्लास्टिक स्ट्रॉ के कारगर विकल्प तलाशने में दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में जल्द ही कारगर विकल्प नहीं मिलने पर इन उत्पादों की आपूर्ति बाधित हो सकती है।

पिछले साल ही की गई थी घोषणा

सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इस तथ्य को सभी जानते हैं। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रहा था। पिछले साल सरकार ने मजबूत फैसला लेते हुए सिंगल यूज वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हुई थी। यही निर्णय एक जुलाई 2022 से अमल में आया।

मदर डेयरी की हो चुकी है तैयारी

दुग्ध तथा कुछ कृषि उत्पाद बेचने वाली कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजेटेबल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनीष बंदलिश ने कहा है कि वह नए नियमों को अपना चुके हैं। एक जुलाई 2022 से बनने वाले उनके हर कार्टन प्रोडक्ट पर प्लास्टिक के नहीं बल्कि आयातित पेपर स्ट्रा चिपके होंगे। हालांकि मदर डेयरी से जब प्लास्टिक और पेपर स्ट्रॉ की कीमतों में अंतर के बारे में पूछा गया तो इस पर कोई जवाब नहीं मिला।

सिगरेट बनाने वाली कंपनियां भी आई आगे

इस बीच सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने भी सिगरेट के पैक पर लगने वाली पतली प्लास्टिक परत के विकल्प के तौर पर प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाने वाली (बायोडिग्रेडेबल) परत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सिगरेट उद्योग की संस्था टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस कदम की प्रशंसा की है। आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां इसकी सदस्य हैं।

सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों के साथ कल बैठक बुलाई, खुदरा कीमतों को नीचे लाने पर होगी चर्चा

नयी दिल्ली। एजेंसी

खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को खाद्य तेल उद्योग निकायों और विनिर्माताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में वैश्विक स्तर पर कीमतों में आई गिरावट के अनुरूप खाने के तेल की खुदरा कीमतों में कमी लाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। यहां राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के इतर खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि खाद्य तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई गई है। इस बारे में संपर्क करने पर सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता ने कहा कि विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के दाम पिछले एक माह में 300 से 450 डॉलर प्रति टन तक घटे हैं। हालांकि, खुदरा बाजार में इसका असर दिखने में कुछ समय लगेगा। मेहता ने कहा कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतें नीचे आएंगी। पांडेय ने 22 जून को कहा था कि खुदरा बाजार में खाद्य तेलों के दाम नीचे आने लगे हैं। पिछले महीने कई खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतों में 10 से 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का 60 प्रतिशत आयात से पूरा करता है।

लागत बढ़ने के बावजूद जून में सेवा गतिविधियां 11 साल के उच्चतम स्तर पर

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अप्रैल 2011 से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। एक मासिक सर्वेक्षण में मंगलवार को बताया गया कि लागत बढ़ने के बावजूद मांग दशाओं में सुधार के चलते यह सुधार हुआ। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक मई में 58.9 से बढ़कर जून में 59.2 हो गया। यह अप्रैल 2011 के बाद का उच्चतम स्तर है। सेवा क्षेत्र में लगातार 11वें महीने में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से अधिक अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से नीचे अंक संकुचन को दर्शाता है। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में संयुक्त निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा कि फरवरी 2011 के बाद से सेवाओं की मांग में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला और आर्थिक गतिविधियों में विस्तार से इसे मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि अगले महीने भी गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान है।

पारद का कड़ा पहनना बेहद लाभकारी

नकारात्मक शक्तियों कई साथ कई बीमारियों को करता है दूर

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

आजकल ज्यादातर लोगों को हाथ में कड़ा पहनना पसंद होता है। कुछ लोग इसे फैशन के तौर पर पहनते हैं तो वहीं कुछ लोग धार्मिक के नजरिए से पहनते हैं। इसका चलन भी काफी पुराना है।वैसे तो कड़ा कई तरह के होते हैं। लोग इसका चुनाव अपने मनपसंद का करते हैं। जहां कुछ लोग सोना, चांदी का कड़ा पहनते हैं तो वहीं कुछ लोग किसी अन्य धातु का लेकिन क्या आपने कभी पारद के कड़े के बारे में सुना हैं? अगर नहीं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पारद के कड़े के बारे में। साथ ही बताएंगे पारद का कड़ा आपके सेहत के लिए किस प्रकार लाभकारी होता है। आइए जानते हैं।

वैदिक धर्मग्रंथों में इसे भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। वहीं ज्योतिष की मानें तो पारद एक जीवंत धातु है अगर इसे हाथ में धारण कर लिया जाए तो ये आपको कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा जीवन में चल रही परेशानियों से भी छुटकारा दिलाता है।

पारद धातु का कड़ा पहनने हैं कई जबरदस्त फायदे नकारात्मक शक्तियां रहती हैं दूर

वैदिक धर्मग्रंथों में पारद धातु को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप इस धातु का कड़ा अपने हाथ में धारण करेंगे तो इससे आपको नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर किसी पर नकारात्मक शक्तियां जल्द हावी हो जाती है तो उन्हें भी इस धातु का कड़ा पहनना चाहिए।

हाथ-पैर और कमर दर्द में असरदार

आजकल अधिकतर लोगों को हाथ-पैर और कमर में दर्द की

शिकायत रहती हैं तो ऐसे में उन्हें पारद का कड़ा पहनना फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि पारद धातु ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में सहायक होता है। ऐसे में इसे धारण करने से आपको दर्द से राहत मिल सकती है।

मौसम संबंधी बीमारियां होंगी दूर

वैसे लोग जो मौसम संबंधी बीमारियों की गिरफ्त में जल्दी आ जाते हैं उन्हें इन बीमारियों से बचने के लिए पारद धातु का कड़ा पहनना चाहिए।

मानसिक पीड़ा और तनाव करता है दूर

जी हां, पारद का कड़ा पहनने से मानसिक पीड़ा भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं इसे पहनने से आलस्य भी दूर हो जाता है।

चातुर्मास से जुड़ी परंपराएं

चातुर्मास में क्यों नहीं होते हैं विवाह जैसे मांगलिक कर्म के मुहूर्त, इन दिनों में कौन-कौन से शुभ काम करना चाहिए

10 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और इस तिथि के बाद से देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास रहेंगे। पंचांग भेद की वजह से देवउठनी एकादशी 4 और 5 नवंबर रहेगी। धर्म और स्वास्थ्य के नजरिए से चातुर्मास का महत्व काफी अधिक है। इन चार महीनों में धर्म-कर्म के साथ ही दैनिक जीवन में काफी सावधानी रखनी चाहिए।

इंदौर के ज्योतिषाचार्य श्री रघुनंदन जी के मुताबिक अभी बारिश का समय है और इस वजह से खाने-पीने की चीजों के संबंध में की गई लापरवाही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। बादलों की वजह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं होंगे। धूप नहीं निकलेगी, इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर होता है। इसलिए मांसाहार, अधिक तेल-मसालेदार खाने से बचना चाहिए। ऐसी चीजों का सेवन करें, जिन्हें हमारा पाचन तंत्र आसानी से पचा सकता है।

चातुर्मास में विष्णु जी करते हैं विश्राम

विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कर्मों में पंचदेवों की पूजा खासतौर पर की जाती है। पंचदेवों में गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा और सूर्य देव शामिल हैं।

मान्यता है कि चातुर्मास में विष्णु जी विश्राम करते हैं और इस वजह से वे किसी भी शुभ कर्म में उपस्थित नहीं होते हैं।

विष्णु जी की अनुपस्थिति में कोई भी शुभ कर्म नहीं हो सकता है। इसी मान्यता की वजह से चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहते हैं।

चातुर्मास में कौन-कौन से शुभ कर्म करें

चातुर्मास में अपने इष्टदेव के मंत्रों का जप और ध्यान करना चाहिए। इन दिनों में रामायण, श्रीमद् भगवद् गीता, शिव पुराण जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए।

शिवलिंग पर चांदी के लोटे से दूध चढ़ाएं और ऊँ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। विष्णु जी के मंत्र ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, आप चाहें तो श्रीकृष्ण के मंत्र कृं कृष्णाय नमः का भी जप कर सकते हैं।

इन दिनों में कई लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति में जरूरतमंद लोगों की मदद करें। धन, अनाज, वस्त्र, जूते-चप्पल और छाते का दान करें। गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें।

शनि की उल्टी चालः 13 जुलाई को मकर में प्रवेश करेगा

फिर शुरू होगी धनु राशि वालों पर साढ़ेसाती; मिथुन और तुला पर रहेगी ढय्या

श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तविद अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

13 जुलाई को शनि वक्री रहते हुए एक राशि पीछे की ओर आ जाएगा। यानी फिर से मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। जिससे कई लोगों पर साढ़ेसाती और ढय्या शुरू होगी। वहीं, कुछ लोगों को इससे राहत मिलेगी। अब पूरे साल शनि मकर राशि में ही रहेगा। इसके बाद 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा।

इन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती

इंदौर के ज्योतिषाचार्य श्री रघुनंदन जी बताते हैं कि मकर में शनि के आने से धनु राशि वालों पर फिर से साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी और मीन राशि वालों को इससे राहत मिलेगी। धनु राशि वालों पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण है यानी पूरे साल शनि का शुभ फल मिलेगा। वहीं मकर और कुंभ राशि वालों पर भी शनि की साढ़ेसाती रहेगी। इन दोनों राशियों के लोगों को नौकरी, बिजनेस और सेहत को लेकर सावधान रहना होगा।

शनि की ढैय्या

श्री रघुनंदन जी के मुताबिक वर्तमान में कर्क और वृश्चिक राशि वाले लोगों पर शनि की ढय्या चल रही है। शनि के मकर राशि में आते ही मिथुन और तुला राशि वालों पर शनि की ढय्या शुरू हो जाएगी। यानी मिथुन राशि के लिए गोचर कुंडली में शनि अष्टम भाव में आ जाएगा और तुला राशि वालों पर शनि की टेढ़ी नजर रहेगी। इस वजह से इन 2 राशियों के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

किन राशियों पर रहेगी शनि की नजर

मकर राशि में शनि के आ जाने से कर्क राशि वालों पर शनि की सीधी दृष्टि रहेगी। हालांकि इससे कर्क राशि वालों के लिए समय मिला-जुला रहेगा, लेकिन तुला राशि पर शनि की टेढ़ी नजर होने से इस राशि के लोगों के कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। धन हानि और दौड़-भाग के भी योग बनेंगे। मेहनत भी ज्यादा होगी। वहीं मीन राशि वालों पर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी, लेकिन इसका कोई खास अशुभ प्रभाव नहीं होगा।

7 राशियां होंगी प्रभावित

श्री रघुनंदन जी का कहना है कि शनि के राशि बदलने से कई लोग इसके शुभ-अशुभ असर से प्रभावित होंगे। शनि के राशि परिवर्तन का असर खासतौर से धनु, मकर, कुंभ, मीन, मिथुन, कर्क और तुला राशि वालों पर पड़ेगा। शनि के कारण इन 7 राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव होने की संभावना है। इनके अलावा शनि देव अन्य 5 राशियों को भी किसी न किसी तरह प्रभावित करेंगे।

आषाढ़ में वामन पूजा की परंपराःइस महीने के गुरुवार को व्रत रखने और भगवान वामन की पूजा करने से खत्म होते हैं पाप

स्कंद पुराण के मुताबिक आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि इस महीने के देवता भगवान वामन ही हैं। इसलिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान वामन की विशेष पूजा और व्रत की परंपरा है। वामन पुराण के मुताबिक आषाढ़ महीने के दौरान भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान सुख मिलता है, जाने-अनजाने में हुए पाप और शारीरिक परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं।

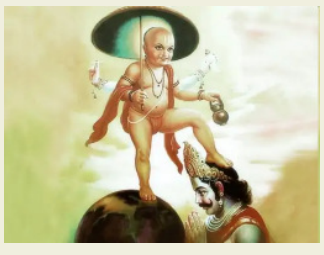

गुरुवार को विशेष पूजा और व्रत

ग्रंथों में आषाढ़ महीने के गुरुवार को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत और पूजा के बाद छोटे बच्चे को भगवान वामन का रूप मानकर भोजन करवाया जाता है और जरूरत की चीजों का दान भी किया जाता है। साथ ही इस महीने की दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान वामन की पूजा के बाद अन्न और जल का दान किया जाता है।

क्या था वामन अवतार

सतयुग में असुर बलि ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के मदद मांगने पहुंचे। तब विष्णुजी ने देवमाता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। इसके बाद एक दिन राजा बलि यज्ञ कर रहा था, तब वामन देव बलि के पास गए और तीन पग धरती दान में मांगी। शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी राजा बलि ने वामन देव को तीन पग धरती दान में देने का वचन दे दिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण किया और एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने वामन को खुद सिर पर पग रखने को कहा। वामनदेव ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा, वह पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पाताललोक का स्वामी बना दिया और सभी देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दिया।

भारत की सबसे ज्यादा सराही गई एसयूवी, अब हॉट एवं टेकी अवतार में

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे चहेती कंपैक्ट एसयूवी, ब्रेज़्ज़ा के ऑल-न्यू फीचर पैक्ड हॉट एवं टेकी अवतार के लॉन्च की घोषणा की। आज के ट्रेंड के अनुरूप, ऑल-न्यू हॉट एवं टेकी ब्रेज़्ज़ा में अनेक अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी और नैक्स्ट जनरशन का कम्फर्ट व सुविधाएं हैं। यह शहरों की एसयूवी स्टाईलिश एवं आकर्षक नए डिज़ाईन के साथ शक्तिशाली परफॉर्मेंस और अत्याधुनिक सुरक्षा विशेषताएं प्रदान करती है।

आलोचकों और ग्राहकों द्वारा समान रूप से सराही गई, ब्रेज़्ज़ा भारत की सबसे पसंदीदा कंपैक्ट एसयूवी है। ब्रेज़्ज़ा हमेशा से न केवल मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में, बल्कि अपनी श्रेणी में भी एक लोकप्रिय एसयूवी बनी हुई है। इसमें हाई-टेक विशेषताएं हैं, जो शहरों में घूमने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसीलिए इस लोकप्रिय कंपैक्ट एसयूवी को ऑल-न्यू हॉट एंड टेकी ब्रेज़्ज़ा - सिटी ब्रेड एसयूवी कहा जाता है।

ऑल न्यू हॉट एंड टेकी ब्रेज़्ज़ा के लॉन्च के बारे में, श्री हिसाशी ताकेयुची, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कहा, ''भारत में कंसैप्चुअलाईज़, डिज़ाईन और विकसित की गई ब्रेज़्ज़ा अपने स्टाईलिश डिज़ाईन, बोल्ड स्टांस और सड़क पर दमदार मौजूदगी के साथ भारत में कंपैक्ट एसयूवी के सेगमेंट को परिभाषित करती है। सबसे चहेती कंपैक्ट एसयूवी ब्रेज़्ज़ा अपने 7,50,000 संतुष्ट ग्राहकों के साथ सेल्स की तालिका में निरंतर अपना वर्चस्व बनाए हुए है और सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 पैसेंजर वाहनों में से एक है। ब्रेज़्ज़ा ने उन ग्राहकों को आकर्षित किया है, जो अपने व्यक्तित्व के अनुसार एक स्टाईलिश एसयूवी चाहते हैं। महत्वाकांक्षी ग्राहकों के लिए 'मोबिलिटी की खुशी' बढ़ाने के उद्देश्य से आज हम नए ऊर्जस्वी डिज़ाईन, अगली जनरेशन की खूबियों और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ''ऑल न्यू हॉट एंड टेकी ब्रेज़्ज़ा'' प्रस्तुत करके बहुत उत्साहित हैं, जो ग्राहकों की अपेक्षाओं से भी बढ़कर है। हमें वि'वास है कि ग्राहक ऑल-न्यू ब्रेज़्ज़ा को पसंद करेंगे और यह फिर से ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल करेगी।''

हीरो मोटोकॉर्प ने पैशन में तकनीकी खूबियों को जोड़ा

कई अत्याधुनिक 'कनेक्टेड' फीचर्स के साथ लॉन्च की पैशन 'एक्सटेक'

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

दुनिया में मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के सबसे बड़े निर्माता, हीरो मोटोकॉर्प, ने उत्पादों के आधुनिकीकरण की आक्रामक रणनीति को बरकरार रखते हुए आज नई पैशन 'एक्सटेक' को लॉन्च किया। पैशन एक्सटेक मोटरसाइकिल देश भर के हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप्स पर उपलब्ध है और इसके ड्रम वैरिएंट की आकर्षक कीमत 74,590 रुपयेङ, जबकि डिस्क वैरिएंट की कीमत 78,990 रुपयेङ है। पैशन एक्सटेक 5 साल की वारंटी के साथ आती है जोकि ब्रांड के विश्वास और भरोसे को दोहराता है।

नई हीरो पैशन 'एक्सटेक' स्टाइल, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आराम का बेहतरीन संयोजन है। यह मोटरसाइकिल कई फीचर्स से लैस है, जिसमें अपने सेग्मेंट में पहली बार प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप, ब्लूटुथ कनेक्टिविटी के साथ फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क?लस्टर, एसएमएस और कॉल अलर्ट, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, लो फ?यूल इंडिकेटर, साइज-स्टैंड इंजन कट ऑफ और सर्विस रिमाइंडर शामिल है। अपने सेग्मेंट में पहली बार शामिल फीचर्स और पैशन ब्रैंड के प्रति विश्वास और भरोसे ने पैशन एक्सटेक बाइक को इस श्रेणी में आने वाली दूसरी बाइक्स से अलग खड़ा कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प में स?ट्रैटेजी विभाग के हेड और ग्लोबल प्रॉडक्ट प्लानिंग के हेड मालो ली मैसन ने कहा, 'नए फीचर्स और स्मार्ट डिजाइन के साथ मिलने वाली पैशन एक्सटेक ऐसा आकर्षक उत?पाद है, जो देश भर के नौजवानों को अपनी और आकर्षित करेगा। हमारे 'एक्सटेक' प्रॉडक्ट्स की रेंज, जिसमें स्पेंलडरहएक्सटेक, ग्लैमर 125 एक्सटेक, प्लेज़रह110 एक्सटेक और डेस्टिनी 125 एक्सटेक शामिल हैं, को उपभोक्ताओं की ओर से काफी बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। हमें यह पूरी उम्मीद है कि पैशन एक्सटेक इस ट्रेंड को बरकरार रखेगी।'

हीरो मोटोकॉर्प में चीफ ग्रोथ ऑफिसर रणजीवजीत सिंह ने कहा, 'हीरो मोटोकॉर्प एक शानदार और प्रतिष्ठित ब्रांड है। इसे दशकों से उपभोक्ताओं के बहुत बड़े वर्ग का विश्वास हासिल है। अपने नए स्टाइल और नए नजरिये से पैशन टेक नई उम्र के बाइक सवारों को अपनी और आकर्षित करेगी। इसी के साथ यह अपने आधुनिक फीचर्स के साथ इस श्रेणी में नए मानदंड तय करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि पैशन एक्सटेक देश में मोटरसाइकिल की श्रेणी में हमारी नेतृत्व की स्थिति को और मजबूत करने में हमें सक्षम बनाएगी।' आज की पीढ़ी के लिए डिजाइन की गई दमदार परफॉर्मेंस देने वाली और मजबूत नई 110 सीसी पैशन एक्सटेक बाइक सुविधा, सुरक्षा और उपयोगिता के कई फीचर्स से लैस है, जो बिना किसी परेशानी के यूजर्स को बेहतरीन राइडिंग के अनुभव को सहज रूप से एकीकृत करती है।

दूरसंचार विभाग ने वायरलेस जैमर, नेटवर्क बूस्टर की अवैध बिक्री पर ई-कॉमर्स कंपनियों को चेताया

नयी दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने ई-कॉमर्स कंपनियों को वायरलेस जैमर और नेटवर्क बूस्टर जैसे कुछ दूरसंचार उपकरण बेचने के प्रति आगाह किया है। इस तरह के उपकरण बेचने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। सोमवार को एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई है। दूरसंचार विभाग ने पिछले 4-5 साल में कई बार इस मुद्दे को उठाया है और यहां तक कि इन उपकरणों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी भी की है। दूरसंचार विभाग ने बयान में कहा, ''सेल्युलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जाम करने वाले उपकरणों का उपयोग आम तौर पर अवैध है, बशर्ते कि सरकार द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति न दी गई हो। कोई निजी कंपनी या निजी व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद या उसका उपयोग नहीं कर सकता।'' विभाग ने कहा कि भारत में सिग्नल रोकने वाले उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या बाजार में इसकी बिक्री करने के संबंध में कोई संकेत देना गैरकानूनी है। उपरोक्त नोटिस की एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीमा शुल्क विभाग को भी उचित कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। दूरसंचार उद्योग निकाय, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा है कि आम लोग इस बात से अनजान हैं कि वायरलेस टेलीग्राफी कानून, 1933 और इंडिया टेलीग्राफ कानून, 1885 के तहत मोबाइल सिग्नल बूस्टर (एमएसबी) खरीदना, बेचना, लगाना और रखना एक अवैध और दंडनीय अपराध है।

एसवी बीस्पोक एडिशन 1988 : जगुआर की रेसिंग सफलता से एफ-पेस एसवीआर के लिमिटेड एडिशन

दुनिया में एफ-पेस एसवीआर एडिशन 1988 की केवल 394 गाड़ियां बनाई जाएंगी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

एक्सक्लूसिव एफ-पेस एसवीआर एडिशन 1988 जगुआर एसयूवी की शानदार परफॉर्मेंस वाली एसयूवी का पहला लिमिटेड एडिशन है। उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर इसे एसवी बीस्पोक में बनाया गया है। दुनिया भर में इस मॉडल की केवल 394 एसयूवी उपलब्ध हैं।

जगुआर की रेसिंग कारों की समृद्ध विरासत से प्रेरित होकर भावनात्मक विशेषता वाली एसयूवी में खासतौर से मिडनाइट एमेथिस्ट पेंट किया है। इसमें वैकल्पिक रूप से शैपेंन गोल्ड साटन रंगों में ठोस अल्यूमीनियम धातु से निर्मित 55.88 सेमी के मिश्र धातु के पहिये लगाए गए हैं। इसके बाहरी और भीतरी भाग पर सनसेट गोल्ड साटन कलर का विस्तार किया गया है । इसके साथ ही उपभोक्ताओं को इस एसयूवी में एसवी बीस्पोक का शानदार कारीगरी से निर्मित ग्राफिक 'वन ऑफ 394' भी लिखा मिलेगा।

इस एसयूवी को एडिशन 1988 नाम 1988 की वर्ल्ड स्पोर्ट्स प्रोटोटाइप चैंपियनशप की विजेता कार एक्सजेआर-9 की रेसिंग में मिली सफलता को याद करते हुए दिया गया है। जगुआर में स्पेशल व्हीकल्स ऑपरेशंस के कमर्शल डायरेक्टर मार्क टर्नर ने कहा, '2019 में लॉन्च किए जाने के बाद से जगुआर एफ-पेस एसवीआर ने खुद को जबर्दस्त चरित्र की बेहतरीन और शानदार हाई परफॉर्मेंस कार के रूप में खुद को स्थापित किया है। एसयूवी की इन विशेषताओं के साथ इसमें एसवी बेस्पोक के विशेषज्ञों की ओर से उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई फीचर्स जोड़े हैं। इससे पहले एसयूवी में इतनी विशेषताएं नहीं दी गई थीं, जो इस गाड़ी में दी गई हैं। इससे एफ-पेस एडिशन 1988 और अधिक सम्मोहित कर उपभोक्ताओं को अपनी और आकर्षित करती है।

जगुआर के स्पेशल व्हीकल ऑपरेशंस विभाग के क्रिएटिव डायरेक्टर रिचर्ड वूली ने कहा, 'एफ-पेस एसवीआर एडिशन 1988 का डिजाइन जगुआर की बेहद सहनशीलता वाली ऐतिहासिक रेसिंग कारों से प्रेरित है। कार पर किया गया मिडनाइट एमेथिस्ट ग्लास पेंटवर्क तब तक काला नजर जाता है, जब तक इस कार पर सूरज की चमकती किरणें नहीं पड़ती। इससे एसवीआर के बाहरी भाग की खूबसूरती और गतिशीलता और बढ़ जाती है। इस नाटकीय अल्ट्रा मैटेलिक ग्लॉस फिनिश को हसिल करने के लिए कंपनी ने अपने मनचाहे गहरे रंग को निर्मित करने के लिए 40 से ज्यादा वैरिएशंस का आकलन किया है।'

एडिशन 1988 ने अनूठे ढंग से सनसेट गोल्ड सैटिन जगुआर लीपर और टेलगेट पर स्क्रिप्ट को दिया है। हर फ्रंट विंग पैनल पर लेजर का नक्काशी से उभारा गया एडिशन 1988 का लोगो भी मिलता है। एफ-पेस एसवीआर के ब्लैक पैक कंपोनेंट्स के अलावा ग्लॉस ब्लैक फिनिश का विस्तार एसयूवी के दरवाजे की मिरर कैप, ब्रेक कैलिपर्स, व्हील सेंटर कैप्स और एसवीआर बैज के आर लेटर पर भी मिलता है।

जगुआर में व्हील पर्सनलाइजेशन के निदेशक मार्क वाइक्स ने कहा, 'एडिशन 1988 हमारे बीस्पोक से शुरू हुआ। इन कारों के निर्माण में जगुआर की डिजाइनिंग टीम ने पूर्व में रेस में विजेता रही प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स कारों से प्रेरणा ली है। इसके नतीजों के तौर पर हमें तरह-तरह के रंग, आकार और फीचर्स का संगम मिला है, जो स्पोर्ट्स कारों की सफलता का जश्न मनाने के साथ एफ-पेस एसवीआर को और ज्यादा आकर्षक बनाता है।' एफ-पेस एसवीआर जगुआर की जबर्दस्त परफॉर्मेंस देने वाली एसयूवी है। यह जगुआर 5.0 । वी8 के सुपरचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से पावर्ड है। यह केवल चार सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। स्पेशल व्हीकल ऑपरेशंस के विशेषज्ञों की टीम की ओर से निर्मित और विकसित किए गए तकनीकी अपग्रेडेशन का पूरा पैकेज एफ-पेस एसवीआर की शानदार परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। यह इसे रोजाना इस्तेमाल करने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता।

डी बीयर्स ने मुंबई में अपने वार्षिक फोरम का आयोजन किया

अवंती कलेक्शन' में नए डिजाइनों के लॉन्च की घोषणा

ब्रांड की टैगलाइन 'ए डायमंड इज़ फॉरएवर' की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी, डी बीयर्स ग्रुप ने इस हफ्ते मुंबई में अपने वार्षिक फोरम का आयोजन किया। इस फोरम में देश भर के सभी अधिकृत भागीदारों, हीरा कारोबारियों, आभूषण निर्माताओं के साथ-साथ डी बीयर्स ग्लोबल टीम में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। तीन दिनों के लिए आयोजित इस फोरम का मुख्य उद्देश्य, डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े सदस्यों को ब्रांड के विकास एवं विजन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर प्राकृतिक हीरा उद्योग की प्रगति पर आपस में चर्चा करने, नेटवर्क बनाने और गहन जानकारी वाली बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना था।

इस साल की थीम में डी बीयर्स की सबसे ऐतिहासिक टैगलाइन, 'ए डायमंड इज़ फॉरएवर' को शामिल किया गया है, जिसने कहानी बयां करने वाले एक शानदार माध्यम के रूप में हमेशा ब्रांड की विरासत को आगे बढ़ाया है। इस साल इस आइकॉनिक टैगलाइन की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

इस मौके पर डी बीयर्स ब्रांड्स के सीईओ, मार्क जैचेट ने कहा, 'भारत ने दुनिया भर की डायमंड इंडस्ट्री में बेहद अहम भूमिका निभाई है और यह फोरम हमें अपने अधिकृत भागीदारों के साथ जुड़ने में मदद करता है।

इस फोरम के दौरान, ब्रांड ने फॉरएवरमार्क अवंती कलेक्शन में नए डिजाइनों के लॉन्च की घोषणा भी की। इस मॉडर्न कलेक्शन की प्रगति में एक नवीनतम अध्याय जोड़ा गया है, जिसके बिल्कुल नए डिजाइन नई संभावनाओं के मूल भाव को दर्शाते हैं, साथ ही पहनने वाले को अपनी शक्ति का एहसास करने और हर दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने की प्रेरणा देते हैं। इस कलेक्शन की एकदम नई अंगूठियों, पेंडेंट और झुमके में सबसे खूबसूरत, नायाब तथा जिम्मेदारी से प्राप्त किए गए डी बीयर्स फॉरएवरमार्क डायमंड को 18 कैरेट के यलो, ह्वाइट या रोज गोल्ड में सेट किया गया है। नगीने के रूप में जड़े गए डायमंड्स की अतिरिक्त चमक के साथ बिल्कुल साफ़-सुथरे एवं नई ऊर्जा देने वाले शानदार डिजाइन भी उपलब्ध हैं।

श्री सचिन जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डी बीयर्स इंडिया, ने कहा, 'डी बीयर्स ग्रुप ने वर्षों से, हर तरह के उतार-चढ़ावों के साथ-साथ बदलती परिस्थितियों के दौरान भी आईकॉनिक लाइन 'ए डायमंड इज़ फॉरएवर' से प्रेरणा लेना जारी रखा है। इन सब चीजों के बीच, और यहां तक की हाल में आई महामारी के दौर में बाजार के कामकाज के तौर-तरीकों में बदलाव के बावजूद डी बीयर्स लगातार आगे बढ़ता रहा है। हर साल आयोजित होने वाला फोरम हमारे लिए अपने भागीदारों को एकजुट करने, नेटवर्क बनाने और तीन दिनों के दौरान लेन-देन करने का अवसर होता है।

फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सैफरान ग्रुप हैदराबाद, बेंगलुरु में लगाएगा संयंत्र

नयी दिल्ली। एजेंसी

फ्रांस की रक्षा कंपनी सैफरान ग्रुप ने मंगलवार को उन्नत विमान इंजनों के कलपुर्जे बनाने के लिए 3.6 करोड़ यूरो के निवेश से हैदराबाद में एक संयंत्र स्थापित करने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने की घोषणा की। फ्रांसीसी कंपनी भारतीय एवं विदेशी वाणिज्यिक विमानों के लिए हैदराबाद में एक रखरखाव

एवं मरम्मत (एमआरओ) संयंत्र भी लगाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैफरान ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ओलिवर एंड्रीस की बैठक के बाद यह घोषणा की गई।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल के साथ संयुक्त उद्यम बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, जो हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का निर्माण करेगा। यह इंजन मध्यम वजन वाले इंडियन मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (आईएमआरएच) में लगाया जाएगा जिसका विकास एचएएल कर रहा है। सैफरान ग्रुप असैन्य एवं लड़ाकू विमानों के उन्नत इंजनों के असली कलपुर्जे बनाने वाली अग्रणी कंपनी है। सैफरान ग्रुप ने कहा कि एमआरओ सुविधा केंद्र पर 15 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाएगा। यह केंद्र भारतीय एवं विदेशी वाणिज्यिक विमानों में इस्तेमाल होने वाले लीप-1ए और लीप-1बी इंजनों का रखरखाव करेगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह एमआरओ केंद्र शुरुआती दौर में साल भर में 250 से अधिक इंजनों की मरम्मत कर पाने में सक्षम होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान सैफरान ग्रुप के सीईओ ने इस हफ्ते इन तीनों संयंत्रों के उद्घाटन के बारे में भी चर्चा की। हैदराबाद में विमान इंजन कलपुर्जा संयंत्र और एमआरओ सुविधा केंद्र के अलावा बेंगलुरु में सैफरान-एचएएल संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाना है। इस मुलाकात में रक्षा मंत्री ने सैफरान को भारत में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण एवं विकास के लिए नए उद्यम लगाने का न्योता देते हुए कहा कि इससे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बल मिलेगा। सिंह ने कहा, "हमारा एक बड़ा बाजार हैं। हमारा जोर प्रतिस्पर्धी ढंग से जरूरतें पूरा करने के लिए भारत में निर्माण करने और मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों को आपूर्ति करने पर है।" इस संदर्भ में सैफरान ग्रुप ने कहा, "हैदराबाद के एसईजेड में 10 एकड़ भूभाग में 3.6 करोड़ यूरो के निवेश से सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स स्थापित किया जाएगा। यह उन्नत विमानों के इंजन के कलपुर्जे बनाएगा।" वहीं हैदराबाद में ही प्रस्तावित सैफरान इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड असैन्य एवं लड़ाकू विमानों के कलपुर्जों का निर्माण करेगी।

नौसेना डेक आधारित विमानों की खरीद करेगी

नयी दिल्ली। स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत के लिए भारतीय नौसेना सरकार से सरकार के स्तर पर डेक आधारित विमानों के बेड़े की खरीद की प्रक्रिया में है। इस मामले से परिचित लोगों ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि नौसेना ने खरीद के लिए बोइंग के एफ/ए-18 ई हार्नेट और फ्रांसीसी कंपनी 'दसॉल्ट एविएशन' के राफेल एम विमान को चयनित किया गया है।

इन दोनों विमानों ने गोवा स्थित नौसैनिक अड्डे पर अपनी संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया है। नौसेना अब इन दोनों विमानों के प्रदर्शन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस बारे में जानकारी देने वाले उक्त लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, "रिपोर्ट के आधार पर हम खरीद प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि विमानों की खरीद सरकार से सरकार के स्तर पर तैयार ढांचे के तहत होगी। गत मई में दो बोइंग एफ/ए-18ई सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने गोवा स्थित नौसैनिक अड्डे पर अपनी परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया, जबकि इसी तरह का अभ्यास जनवरी में राफेल समुद्री लड़ाकू विमान द्वारा किया गया था।

नौसेना के वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने खरीद के बारे में पूछे जाने पर कहा, "परीक्षण किया जा रहा है, नौसेना को ऐसे विमानों की आवश्यकता है जो विमान वाहक पोत से उड़ान भर सकें।" चार साल पहले भारतीय नौसेना ने अपने विमानवाहक पोत के लिए 57 बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमान हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि पता चला है कि शुरुआत में यह संख्या 30 के आसपास हो सकती है। भारतीय नौसेना विमान वाहक पोत विक्रांत के लिए डेक-आधारित विमान खरीदने की योजना बना रही है, जिसकी तैनाती अगस्त में होने की संभावना है। वर्तमान में नौसेना अपने एकमात्र विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य से रूसी मूल के मिग-29के लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। डेक आधारित लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए नौसेना द्वारा जारी सूचना अनुरोध में यह जानकारी मांगी गई है कि कंपनियां भारत के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को किस स्तर पर साझा करने की इच्छुक हैं।

चिप आपूर्ति में सुधार से यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री जून में 40 प्रतिशत बढ़ी

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री जून में 40 प्रतिशत बढ़ी, जिससे सेमीकंडक्टर आपूर्ति में सुधार का संकेत मिलता है। खासकर एसयूवी खंड के लिए मांग मजबूत बनी हुई है। ऑटो डीलरों के निकाय फाडा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार यात्री वाहनों (पीवी) का पंजीकरण

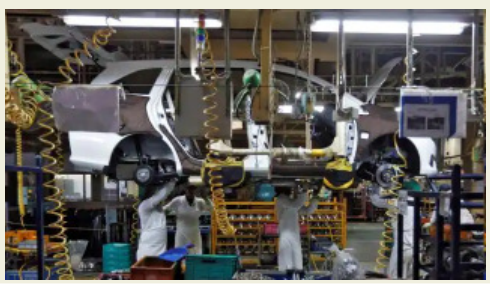

पिछले महीने सालाना आधार पर 40 प्रतिशत बढ़कर 2,60,683 इकाई हो गया, जबकि जून 2021 में यह आंकड़ा 1,85,998 इकाई था।

फाडा के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने एक बयान में कहा, "यात्री वाहन खंड में मजबूत वृद्धि देखी जा रही है। आपूर्ति में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सेमीकंडक्टर उपलब्धता अब बढ़ रही है।" उन्होंने कहा कि चिप की कमी के कारण खासतौर से कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी खंड में प्रतीक्षा अवधि अधिक बनी हुई है। फाडा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 20 प्रतिशत बढ़कर 11,19,096 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले की इस अवधि में यह 9,30,825 इकाई थी। वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री में भी पिछले महीने सालाना आधार पर 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।